

चन्द्रमोहन भगत

राज्यों संभागों और जिलों की एकदशक यातायात मंदसौर को संभाग कभी का बन जाना था। इस जिले से अविभाजित मध्य प्रदेश को दो मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र सकलेश व मिला थे। दोनों ही जनसंघ से लेकर भाजपा के कद्दावर नेता और दृढ़ इच्छा शक्ति धारक नेता थे। तब अगर यह मांग उठी होती तो शायद आज उज्जैन के मुकाबले मंदसौर स्थापित संभाग विहित किया जाता!

ऐसा ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि जिलों को बनाने में भौगोलिक और राजस्व दृष्टिकोण से ज्यादा महत्व दिया जाता है क्षेत्र के राजनीतिक राजनेताओं की हैसियत को। जिलों के मामलों में उदाहरण के तौर पर दत्तिया सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र वाला जिला है, यहां भाजपा शासन काल में नरोत्तम मिश्रा

जैसे कद्दावर नेता प्रदेश के गृहमंत्री रह चुके हैं। आगरा जिला भी मात्र दो विधानसभा आगरा और सुसनेर को मिलाकर बनाया गया है। हरदोई भी हरदोई और टिप्पनी से बना है। स्पष्ट है कि ऐसे विभाजन या निर्माण में सबसे शक्तिशाली दृष्टिकोण राजनेताओं की हैसियत पर निर्भर करता है न कि भौगोलिक या राजस्व दृष्टिकोण। बीच के दिनों में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाट्टा का बयान आया था कि उनकी मांग थी, जब नीमच अलग जिला घोषित किया था तभी मंदसौर को संभाग का आकार मिल जाना था। तत्समय नरेंद्र नाट्टा, सुभाष सोजितिया, घनश्याम पाटीदार, महेंद्र सिंह कालूखंडा सरकार में मंत्री रहे थे। किसने रोका था! साफ कहें तो प्रतिस्पर्धा की हैसियत बढी हुई थी। वरना चार मंत्री वाला संसदीय क्षेत्र संभाग न बन गया होता।

पर नरोत्तम मिश्रा जैसा जज्बा नहीं था कि मात्र एक विधानसभा का जिला दत्तिया बना दिया था। इन उदाहरणों के प्रसंगवश सरकार के प्रतिनिधियों के लिए किसी शायर की ये पंक्तियां कही जा सकती हैं कि

‘आप बस किरदार हैं अपनी हैसियत पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकल जाएंगे।’

अब भी मंदसौर का संभाग बन जाना हर दृष्टि से जायज मांग है, जनमत की मांग लगातार जारी है। बस राजनेताओं को अपनी राजनीतिक हैसियत का सामूहिक परिचय देकर घोषित कराना बाकी है। अपनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को हाशिए पर रख एक ही दल के दो सांसद, सात विधायक अगर एक हैसियत बनाकर सरकार से मांग कर बैठें तो समझो मंदसौर, संभाग बन ही गया...



वित्तपोषण करने वालों पर नकूल कसी जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोगों को सलाहों के पीछे डाला जा चुका है, हजारों बैंक खाते बंद किए जा चुके हैं। सीमा पर ये जिन रास्तों से दहशतगर्दों को मदद मिल सकती थी, वे सारे बंद कर दिए गए हैं। इन वर्षों में बहुत सारे दहशतगर्द और उनके सरगना मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद अगर वहाँ लिखित हिंसा का सिलसिला रुक नहीं रहा, सुरक्षा बलों पर घात लगा कर हमले कम नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? छिपी बात नहीं है कि घाटों में दहशतगर्दों को पोसने में पाकिस्तान का हाथ है, अगर पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि

मारने के बजाय पकड़ कर उनमें पूछताछ की जानी चाहिए कि वे किसकी राह पर काम कर रहे हैं। फासुक अब्दुल्ला ने यह भी शक जाहिर किया है कि नई सरकार बनने के बाद आतंकी हमले तेज होने के पीछे उनकी पार्टी की सरकार गिराने की साजिश भी हो सकती है। आतंकवाद को किसी सिपायी चरमे से नहीं देखा जाना चाहिए। इस तरह उसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान कमजोर पड़ते हैं। अब जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनी है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह केन्द्र के साथ मिल कर इस समस्या से पार पाने की रणनीति तैयार करेगी और समन्वित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।

ऑनलाइन खाने का तेजी से बढ़ रहा चलन...

A large group of men, mostly in white shirts and dark trousers, are marching in a procession on a street. Some are carrying wooden poles or flags. The scene is outdoors, and the men appear to be of various ages.

बताता है कि भारत वर्ष में जो भी जन्मा है, वह हिंदू है। तीन देशों की सीमाओं में बँट चुका भारत में मौलिक रूप से कोई एक हिंदू है ही नहीं। पाकिस्तान के प्रकाश वसोमी अल्लाफ का दबीत दीपावली के दिन एक्स पर चर्चा में रहा। जिसमें उन्होंने लिखा था कि काश उनके भी पूर्वज कुछ और तनकर खड़े रहते तो उन्हें भी होनी और दीपावली जैसे उत्साह वाले त्योहार मनाने को मिलते। अपने इस दबीत के जरिए एक तरह से वे जाहिर कर रहे थे कि उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे। संघ इसी विचार को मानता है, भारतीय यानी हिंदू। भारतीय समाज को कभी सांप्रदायिकता के आवरण में बाँटा गया तो कभी जाति की संकेतों से ही चला। संघ अपने जन्म से ही दोनों ही वैचारिकी का विरोध करता रहा है। इसके बावजूद उस पर कभी ब्राह्मणवादी होने तो कभी कुछ का आरोप लगता रहा है। किसी भी संघटना के किसी भी व्यक्ति के निजी तौर पर

ये और वे (गांधी) उनके अनुशासन अमरुत्यता की पूर्ण अनुपस्थिति और कठोर सारंगी से बहुत प्रभावित हुए थे। पहले कर्नाटक और बाद में बिहार में हुई जाति जनगणना के बाद राजनीति का एक हिस्सा पूरे देश में जाति जनगणना करने की लेकर अभियान छेड़े हुए है। भारत में पहली बार जाति जनगणना 1931 में हुई थी। अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल भारत में अपने राज बचाने की कोशिश के रूप किया था। शायद दूसरे विषय युद्ध और स्थानीय आंदोलन की तेजी की वजह से 1941 में जनगणना नहीं हुई। आजादी के बाद 1951 की जनगणना की जब तैयारी चल रही थी तो राजनीति के एक हिस्से ने जाति जनगणना की मांग रखी थी। लेकिन जनगणना के प्रभारी मंत्री के नाते तत्कालीन स्वराष्ट्र मंत्री सरदार पटेल ने इस मांग को खारिज कर दिया था। पटेल का मानना था कि जाति जनगणना से सामाजिक तनाव बढ़ेगा और अंततः एक विखंडन की ही बहाना देगा। कुछ ऐसे ही सोच सच की भी है। हालांकि कुछ दिनों पहले संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने जाति जनगणना का समर्थन किया था। जिससे माना गया था कि संघ भी जाति जनगणना के पक्ष में है। ऐसे सोच रखने वालों ने अंबेडकर के विचारों के अगले हिस्से पर ध्यान नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रशासनिक कार्यों के लिए ऐसे आंकड़े जुटाए जा सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

A collage of various Japanese food items, including sushi, sashimi, and bento boxes, arranged in a grid-like pattern. The images show different types of sushi (maki, nigiri), sashimi (sliced raw fish), and bento boxes (small portions of food in a box). The colors are vibrant, and the food is presented in a clean, appetizing manner.

मध्यमवर्गीय समाज के कुछ लोग इन दिनों अनेक भनकियों को देख-देख कर खुद को उनके जैसा ही दिखावे के धम में कज में डूबते जा रहे जा रहे हैं। मासिक किस्त यानी 'ईएमआई' के भरोसे अपने आप को 'रिच' वाली धनी महसूस करने की मानसिकता में लोग मतवाले हुए जा रहे हैं। इस ख्यामोश से कुछ किशोर और यहाँ तक कि बच्चे भी ग्रस्त दिखते हैं। पिछले दिनों एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली एक शिक्षिका कुछ विशालयय में पढ़ने वाले अपने बच्चे के बारे में अपनी सहेली को दुखी होकर बता रही थी कि मेरे बेटे को शहर के सिमला हॉल में जाकर फिज्म देखना ही पसंद नहीं। उसे किसी माल में जाकर फिज्म देख कर ही संतुष्टि मिलती है और यहाँ जाने के बाद जब तक वह सात सी रुपए वाला बड़ा पापन नहीं खरीद कर न खाएँ, तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। ऐसा वह सिर्फ इसलिए करता है कि तब उसे 'रिच फीलिंग' (अमीर दिखने की अनुभूति) होती है। वह खुद को अनेक भनकियों की श्रेणी में खड़ा पाता है। वह किसी सामान्य दुकान से कपड़े नहीं खरीदता, बल्कि किसी बड़े माल में जाकर मशहूर ब्रांड के पैंट-शर्ट, जूते, घड़ी आदि खरीद कर पहनने का आदी हो चुका है। उसकी माँ आए दिन बेटे की आनलाइन खरीदारी से भी परेशान है। घर में तीन-चार चश्मे पहले से पड़े हुए हैं। मगर उसे मोबाइल में आनलाइन कारोबार वाली किसी वेबसाइट पर कोई नया चश्मा पसंद आ जाया, तो फौरन आर्डर कर देगा। चक्करदार जूते, घड़ी आदि नएर आते ही वह आर्डर कर देगा, भले ही ये सब चीजें उसके पास पहले से ही मौजूद हों। माँ समझती है, पर वह मानता नहीं। इस उद्वेग को सिर्फ संदंभ के तौर पर देखा जा सकता है। सच यह है कि ऐसे बच्चे और उनकी ऐसी सोच-समझ और व्यवहार अब समाज में आम मामलों की तरह देखा जा सकता है। सक्षम तबकों से आने वाले ज्यादातर बच्चे इसी मानसिक ढाँचे के रहत अपना जीवन-चक्र आगे बढ़ा रहे हैं। दिखावा एक सामाजिक मूल्य बनता जा रहा है। मगर इस सबसे बेखबर समाज के दूसरे वर्ग भी दिखावे के इस रोग की गिरफ्त में आ रहे हैं। एक नशा बाहर के खाने का भी है। अब अनेक बच्चों को घर का खाना पसंद नहीं आता, आनलाइन पिज्जा और ठंडे पेय मंगा कर खाना-पीना उसे खुब भाता है। आनलाइन खरीद का नशा अलग है। ऐसे समाज बच्चे हैं, जिनकी माँ की एक बड़ी राशि बेटे की आनलाइन

खरीदारी में चली जाती है। वह बार-बार सम्झौती है, लेकिन अमीर होने के अहसास होने से मार की वजह से यह बात सम्झ नहीं लेती अतः कि माँ को अपनी सीमित तनखाह के भरोसे महीने भर घर चलाना है। माँ की आर्थिक दिक्कत से बेटे का कोई संस्कार नहीं। उसे अपनी अमीर होने की अपभूति की चिंता है। मसलन, कभी-कभी आदिल-रकमी नारे लगाते हैं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, हमारी माँ पूरी हो'। इसी तरह, कुछ बच्चों की जिद रहती है कि भले ही माता-पिता के बैंक खाते में पैसे खत्म हो गए हों, मगर उन्हें जो चीज चाहिए तो वह चाहिए। इस तनाव में माँ को मजबूरी में काई से उधारा मानना पड़ता है। ऐसे अनेक बच्चे मध्यवर्गीय परिवारों में मौजूद हैं, जो आर्थिक हैसियत न होने के बावजूद सिर्फ इसलिए अनाप-शनाप चीजें खरीद लेते हैं कि उनकी 'रिच फीलिंग' बचकर रहे। माता-पिता को कर्ज में डुबोकर बच्चे जब आत्मविश्वास में भरकर कहते हैं कि जब वे कमाने लगेंगे, तो महीना का खरीदेगें, पूरी दुनिया की सैर करेंगे, भले ही अभी पुरानी कार खरीदने की भी आर्थिक हैसियत नहीं हो, मगर अमीरों के सपने देखने में कोई कमी नहीं। एक पिता अपने दो बेटों की इसी मानसिकता से प्रथम श्रेणी कि उसके कारण ही वे कर्ज में डूबे हुए हैं। 'आमदनी अउन्नी, खर्चा रुपैया' वाली स्थिति है। ऐसे अहसास के शिकार ने बच्चे अधिक है। जो पढ़ाई-लिखाई की गंभीरता से नहीं लेते और हर समय स्मार्टफोन में नज़रें गड़ाए रखते हैं। अब तो स्मार्टवाच भी है, जिसमें मनोरंजन के बहुत से इंटरजाम हैं। ऐसे बच्चों की महंगी फेमदाइंग को पूरा करने-करते अधिभावक परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को समझा दो नहीं पाते कि हम तुम्हारे अमीर होने के अहसास को और बढ़ाश नहीं कर सकते। कड़े शब्दों का प्रयोग इसलिए भी नहीं करते कि कहीं इसका दुरूपयोग न हो। आए दिन ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं, जिसमें माँ ने डांट दिया तो लड़का घर से भाग गया।

हाल में एक ग्लोबल स्टडी से पता चला है कि टीएम में काम करना मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है। खासकर भारत में, वर्क फॉर्म होम के मुकाबले वर्क फॉर्म ऑफिस मॉडल अधिकांश लाभदायक पाया गया। मेंटल हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर सहकर्मियों के साथ रिश्ते होते हैं। अमेरिका स्थित एक माइंड रिसर्च ऑर्गनाइजेशन की ओर से हाल में करवाई गई एक ग्लोबल स्टडी की रिपोर्ट ने वर्क कल्चर और मेंटल हेल्थ के रिश्तों पर नए सिरे से रोशनी डाली है। रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब भारत में वर्कलॉड और ऑफिस के तनाव भरे माहौल पर बहस गरम है। खासकर पिछले दिनों पुणे में हुई 26 साल की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मौत ने इस बहस को तेज कर दिया है। कोविड-19 के प्रभावों से वर्क फॉर्म होम मॉडल का चलन बढ़ा था। एंजेलिनी

का एक वग अभी भी इसी को पसंद करता है और कंपनियों को उन्हें ऑफिस बुलाने में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन रिपोर्ट में यह तथ्य स्थापित हुआ है कि अकेले काम करने के बजाय टीम में काम करना मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है। खासकर भारत में वर्क फ्रॉम होम के मुकाबले वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड अपनाने वालों के मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स बेहतर पाए गए। हालांकि अमेरिका और यूरोप में हाइब्रिड मोड (यानी कुछ दिन घर से काम और कुछ ऑफिस से) को सबसे अच्छा पाया गया। वर्क लोड और ऑफिस से माहौल का जहां तक सवाल है तो रिपोर्ट बताती है कि मेंटल हेल्थ इंडिकेटर्स का रिश्ता से बढ़ा

गहरा नाता है। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है सहकर्मियों के साथ रिश्ता। सर्वे में यह बात सामने आई कि वर्कलोड और प्लेजिचर टाइमिंग जैसे फैक्टर भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखता है साथ काम कर रहे लोगों के साथ रिश्ता पॉजिटिव है या नहीं, अपने काम के साथ गर्व का भाव जुड़ा है या नहीं और वर्कलेस पर पूछा है या नहीं। यह रिपोर्ट मेंटल हेल्थ से जुड़ी बहस को वर्क-लाइफ बैलेंस के पारंपरिक दायरे से आगे ले जाती है। इस मुद्दे को पर्सनल लाइफ और प्रफेक्शनल लाइफ के दो अलग-अलग खांचों में देखने की परिपाटी से अलग

यह इस मसले पर संपूर्णता में विचार करती है जिससे यह तथ्य रेखांकित होता है कि मानसिक सेहत का मसला लोगों के साथ हमारे रिश्तों से जुड़ा है जो घर के भी हो सकते हैं और व्यक्ति के भी। व्यक्ति के जिन तनावों की बात अक्सर की जाती है, वे भी काफी हद तक सहकर्मियों के आपसी रिश्तों से निष्पत्ति होते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति पर बढ़ते तनाव के मसले को एंज्वायी-एंज्वायर संबंधों से पूरी तरह काटकर नहीं देखा जा सकता। इसका एक सिरा काम के घंटों और एंज्वायी से एंज्वायर की अपेक्षाओं से भी जुड़ा है ही, लेकिन रिपोर्ट न के कई अन्य अहम पहलुओं की ओर ध्यान खींचा है जो अक्सर बहस में अनेकड़े रह जाते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे व्यक्ति को बेहतर बनाने के प्रयासों में और मजबूती आएगी।

दीवाली में भारत से
ज्यादा पटाखें फूटे होंगे!



8		3		1	6			
	9	1					6	
2	6	4						
			4	6			7	2
	7			3			5	
4	3			5	2			
						1	8	5
	8					7	4	
			1	7		2		3

8	3	6	9	5	7	1	2	4
2	7	1	3	8	4	9	6	5
5	9	4	1	2	6	8	7	3
3	2	7	4	6	1	5	9	8
9	1	8	5	7	3	6	4	2
6	4	5	2	9	8	7	3	1
7	6	2	8	4	5	3	1	9
1	8	9	7	3	2	4	5	6
4	5	3	6	1	9	2	8	7

1		2	3		4	5	6
		7			8		
9	10			11			
12			13			14	15
16			17		18		
19		20		21			
		22					
23				24			

8. मीन कहाँ, तूफ कहाँ (3)
9. दुर्ग, अपरधर, ककरा, बिलारु (2)
10. एक पहार, मीन घेत का सम्या (2)
11. धर्याधारी, गोलकातर अरधारी का पिस्त (3)
12. किल्ला मे सौदों का धर्नार्यव, जकाधर्यव (2)
13. कूल, रोप, रोप, लोभ (2)
14. कल, भाषण (4)
15. धुतराध का दुर्गधन को वह धै कहा जता थ (4)
16. लहपरा, पाधारीत, किल्लभ (2)
17. गधियन, येश, जामा, ड्रिम (4)
18. सौ अरधन होन, अरधर अरुलुल होना (4)
19. न्यौलर कातर, डर्यव कातर (3)

य	र	क	औ	न	म		टी
ह	ह	क	र	न		री	ड
ऐ		ह			म	अ	र
न	क	र		मु	म	न	म
	र		र	अ	क	ग	न
र	अ	क	म	र		न	
र			ग		कि		आ
न	र	य	न		औ	र	न

उपज	आवक बोरी में	न्यूनतम	अधिकतम
मक्का	1000	2124	2450
उखद	80	5901	7401
सोयाबीन	5000	3500	4601
गैहू	3000	2680	3340
चना	132	6011	6671
मसुर	53	5600	6341
धनिया	125	3501	6800
लहसुन	12000	12000	26550
मैथी	345	4200	5901
मुंगफली	4500	3851	5400
अलसी	800	5920	6250
सरसो	115	5250	6150
तारामीरा	1	4650	4650
इसबगोल	82	10000	13000
प्याज	5000	2500	4444
कलौंजी	6	15701	18399
तुलसी बीज	5	14501	20781
डॉलर	24	8201	11900
तिली	13	10800	12551
जौ	1	2550	2550
मटरसुखी	6	4500	5380
असालीया	13	10980	11351
मूंग	1	5001	5001

वोट की राजनीति और गरीबी उन्मूलन वादे, सच्चाई और दूरगामी परिणाम

मंदसौर, 05 नवम्बर गुरु एक्सप्रेस। भारत में राजनीतिक दलों का गरीबों के प्रति सेवा भाव वास्तव में कैसा है, इस पर लंबे समय से बहस होती रही है। हर चुनाव में बड़े-बड़े वादों के साथ गरीबों के लिए मुफ्त की योजनाएं और सुविधाएं देने का एलान किया जाता है, जिसमें मुफ्त बिजली, राशन, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं आदि शामिल हैं। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना जैसी योजनाएं केवल एक राज्य में ही सीमित नहीं हैं; ऐसी योजनाओं का मॉडल अब अन्य राज्यों में भी चुनावों में दोहराया जा रहा है। यह एक गंभीर प्रश्न उठाता है कि क्या इन योजनाओं का उद्देश्य वास्तविक रूप से गरीबी उन्मूलन है, या सिर्फ राजनीतिक लाभ कमाने के एक साधन है।

चुनावी वादे और उनका असल उद्देश्य-भारत में, गरीबी हटाने के नाम पर विभिन्न प्रकार के चुनावी वादे किए जाते हैं। देश के प्रमुख राजनीतिक दलों का यह पैटर्न बन गया है कि चुनाव के पहले गरीबों को लुभाने के लिए मुफ्त की 'रेवडियों' का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया। ऐसे वादे वोट पाने का एक जरिया बन गए हैं, जिससे गरीबों का

मनोबल तो बढ़ता है, लेकिन ये दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन के बजाय अल्पकालिक फायदे तक सीमित रह जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 20% वोट इस प्रकार की योजनाओं से प्रभावित होते हैं। इसके बावजूद, दीर्घकालिक रूप से इससे गरीबों को कोई खास फायदा नहीं पहुंचता है।



नेमीचंद राठौर

मुफ्त की योजनाओं का आर्थिक असर—सरकारें मुफ्त की सुविधाएं देने के लिए अक्सर कर्ज लेती हैं, जिससे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उदाहरण के लिए, 2022 में भारत पर कुल सरकारी कर्ज ऋद्ध का लगभग 90% था। इन मुफ्त योजनाओं की वजह से कर्जदाताओं पर बोझ बढ़ता है और सरकार टैक्स बढ़ाने या पेट्रोल-डीजल जैसे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ाने का सहारा लेती है। इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ता है, विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग पर। इस प्रकार, राजनीतिक दल गरीबों की सेवा के नाम पर उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के बजाय कमजोर कर देते हैं।

स्वास्थ्य और शिक्षा की अनदेखी—एक ओर जहां मुफ्त की योजनाओं का वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर सरकारों का ध्यान कम है। वर्तमान में, भारत का

मुफ्त की योजनाओं के दीर्घकालिक परिणाम—राजनीतिक दलों के मुफ्त की योजनाओं से तत्काल लाभ तो होता है, लेकिन यह गरीबों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाता। दीर्घकालिक परिणाम यह है कि गरीबी समाज सरकार पर निर्भर बनता जा रहा है और आत्मनिर्भरता से कोसों दूर हो रहा है। एक अध्ययन के अनुसार, 2022 में भारत की लगभग 6% आबादी बेहद गरीब थी, जो कि पिछले सालों में हुए तमाम प्रयासों के बावजूद ज्यादा नहीं बदली। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य दीर्घकालिक गरीबी उन्मूलन के बजाय तत्काल वोट प्राप्त करना है। इसके अलावा, मुफ्त की योजनाओं की वजह से युवाओं का मानसिकता भी इस ओर मुड़ा रहा है कि उन्हें मेहनत से अधिक सरकारी योजनाओं का सहारा लेना चाहिए। इससे देश के उत्पादकता दर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही, ये योजनाएं देश की आर्थिक विकास दर को प्रभावित करती हैं, क्योंकि सरकार का धन गलत जगह खर्च हो रहा है।

गरीबी उन्मूलन के सही उपाय, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश—गरीबी उन्मूलन के लिए केवल मुफ्त की योजनाओं पर निर्भर रहने से समस्या

हल नहीं होगी। इसके लिए सरकारों को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक निवेश करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होती हैं। यदि सरकारें शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ती और मुफ्त बनाती हैं, तो यह गरीबों के जीवन में एक स्थायी सुधार ला सकता है। भारत को चाहिए कि वह अपने स्वास्थ्य बजट को बढ़ाकर विकसित देशों की तुलना पर कम से कम 5% तक ले जाए और शिक्षा बजट को 6% से अधिक करे। इसके साथ ही, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूलों को अधिक संसाधन देकर बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में मुफ्त की योजनाओं का लालच देकर वोट पाना राजनीतिक दलों के लिए एक आसान रास्ता बन गया है, लेकिन यह गरीबों की दीर्घकालिक भलाई के लिए हानिकारक है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में उचित निवेश ही गरीबों को सशक्त और आत्मनिर्भर बना सकता है। मुफ्त की रेवडियों गरीबी को खत्म करने का सही तरीका नहीं है, बल्कि गरीबी उन्मूलन के नाम पर एक छलावा है।

श्री प्रेम प्रकाश पंथ के पंचम पिताधिश्वर स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज संत मण्डल के साथ आएंगे

मंदसौर, 05 नवम्बर गुरु एक्सप्रेस। सिन्धी हिन्दू समाज श्री प्रेम प्रकाश पंथ के पंचम पिताध्वेश्वर गदिपति सतगुरु स्वामी भगतप्रकाश जी महाराज संत मण्डल के साथ भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव की पावन धरा मंदसौर में श्री प्रेमप्रकाश आश्रम में पन्द्रह वैवाहिक महोत्सव में दिनांक 17 नवंबर रविवार व 18 नवम्बर सोमवार को पधारेंगे।

इस आशय की जानकारी श्री प्रेम प्रकाश सेवा मण्डली के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शिवानी ने देते हुए बताया कि दो वर्ष के अन्तराल के बाद महाहंडले सतगुरु स्वामी भगतप्रकाश जी महाराज व संत मण्डल पधार रहे हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज व संत मण्डल का अमृत वन हिज्ज ज्ञानगंगा सत्संग व भण्डाला प्रसादी सुबह व शाम होंगे। इस पंच दिवसीय समागम को सफल बनाने हेतु महिला एवं पुरुष सेवाधारी संगत की एक बैठक सन्त श्री शंभूलालजी प्रेमप्रकाशी की अध्यक्षता में श्री प्रेम प्रकाश आश्रम में सम्पन्न हुई। जिसमें सेवाधारियों की सेवाओं को सेवा समितियों में बाँटकर समारोह को सफल एवं यादगार बनाने का संकल्प लिया गया। शिवानी ने बताया कि सतगुरु स्वामी भगतप्रकाशजी महाराज व सन्त मण्डल का दिनांक 17 नवम्बर रविवार को भवानीमण्डी से सड़कमार्ग से होकर प्रातः 9.30 मंदसौर से मंगल प्रवेश होगा।

सबसे पहले यज्ञ हवन में पूर्णाहुति सम्पन्न कर सनातन धर्म के प्रवर्तक आचार्य सतगुरु स्वामी उर्दैरामजी महाराज की प्रेमप्रकाश ध्वजा की पूजा अर्चना कर सनातन धर्म कि ध्वजा फहरायेंगे। तत्पश्चात सन्त मण्डल के सन्त सत्संग-प्रवचनों की अमृतमयी वस्तु करेंगे। शिवानी ने बताया कि दिनांक 17 व 18 नवम्बर को सुबह 10 से दोप. 12.30 एवं शाम 6 से 8 बजे तक सद्गुरु स्वामी उर्दैरामजी महाराज, सद्गुरु सर्वानन्द महाराज, सद्गुरु

दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। बैठक में सन्त श्री शंभूलालजी प्रेम प्रकाशी ने गुरु दरबार की सेवा से सेवाधारी को फल प्राप्ति की महिमा को प्रतिपादित कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में आभार प्रदर्शन महिला मण्डली प्रमुख श्रीमती पुष्पा पमनानी ने प्रकट किया।



बड़े अस्पताल मंदसौर में हो सकती शव वाहन की व्यवस्था-विधायक जैन

मंदसौर, 05 नवम्बर गुरु एक्सप्रेस। विधायक विपिन जैन ने जिला कलेक्टर मंदसौर अदिति गर्ग से मुलाकात कर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों के संबंध में चर्चा कर अवगत कराया है। न जिला चिकित्सालय में शासकीय शव वाहन की व्यवस्था की मांग की ज्ञात हो की मंदसौर जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु जिले भर के मरीजों को रेफर किया जाता है परंतु जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो जाने पर शासकीय शव वाहन नहीं होने से मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और निजी शव वाहनों द्वारा अधिक मात्रा में पैसा वसूला जाता है जिला चिकित्सालय में शासकीय शव वाहन अति आवश्यक है।

कालाखेत को किया जाए अतिक्रमण से मुक्त—मंदसौर स्थित कालाखेत समुदाय द्वारा किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने के संबंध में

भी जैन द्वारा विस्तृत चर्चा की गई है कालाखेत क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र है और वर्षों से सारीया समुदाय के लोगों द्वारा मुलाकात कर मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों के संबंध में चर्चा कर अवगत कराया है। न जिला चिकित्सालय में शासकीय शव वाहन की व्यवस्था की मांग की ज्ञात हो की मंदसौर जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु जिले भर के मरीजों को रेफर किया जाता है परंतु जिला चिकित्सालय में मृत्यु हो जाने पर शासकीय शव वाहन नहीं होने से मध्यमवर्गीय परिवारों को काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और निजी शव वाहनों द्वारा अधिक मात्रा में पैसा वसूला जाता है जिला चिकित्सालय में शासकीय शव वाहन अति आवश्यक है।

भगवान पशुपतिनाथ महादेव की प्रतिमा पर बढ रही दरार और क्षरण को लेकर विस्तृत चर्चा की—श्री जैन ने कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग को अवगत कराया की भगवान पशुपतिनाथ की अष्ठभुजी प्रतिमा पर दरार बढ रही है और उसका क्षरण हो रहा है यह चिंता का विषय है पूर्व में भी मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिमा पर पड रही दरार और क्षरण को रोकने हेतु केमिकल लेप लगाकर सुरक्षित किया गया था परंतु पुनः प्रतिमा पर दरार बढना चिंता का

विषय है इस हेतु विशेषज्ञों व मूर्तिकला के जानकारों और पुरातत्त्वविद की संयुक्त टीम गठित कर प्रतिमा पर पड रही दरार को रोकने हेतु अतिशीघ्र कार्रवाई करने के संबंध में मांग की है। जिला कलेक्टर द्वारा आश्स्त किया गया है कि शीघ्र ही संबंध में कार्य किया जाएगा।

मंदिर परिसर में हो कंपोस्ट पिट यूनिट की स्थापना—वही जैन द्वारा मंदिर परिसर में कंपोस्ट पिट यूनिट की स्थापना की भी मांग की गई है जहां पर पुष्प मालाओं और पत्तियों को संग्रहित कर खाद में परिवर्तित किया जा सकता है और उसका उपयोग मंदिर परिसर में ही स्थित बगीचों में किया जा सकता है इस पर भी जिला कलेक्टर द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धा स्वरुप

श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पमाला, बिलपत्र और पत्तियां चढाई जाती हैं जिन्हे बाद में कचरा गाडी में भर कर अयंन्त फेंक दिया जाता है जो सही नहीं है इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत होती है जैन द्वारा मंदिर परिसर में ही एक छोटी कंपोस्ट पिट यूनिट की स्थापना की मांग की गई है जहां पर पुष्प मालाओं और पत्तियों को संग्रहित कर खाद में परिवर्तित किया जा सकता है और उसका उपयोग मंदिर परिसर में ही स्थित बगीचों में किया जा सकता है इस पर भी जिला कलेक्टर द्वारा सहमति व्यक्ती की गई है।

खाद का तनाव...

गए, लेकिन खाद के लिए फिर लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। किसान प्रेम शंकर ने बताया कि गेहूँ, चना मेथी सहित अन्य फसलों को यूरिया खाद की अधिक जरूरत है। यहां घंटों कतार में लगने के बाद दो बीघा पर 1 बैग यूरिया मिल रहा है।

*** नाम परिवर्तन ***

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं जमीला पति मुस्तफा लोर्ड ने अपना नाम परिवर्तन कर जमीला लोर्ड पति मुस्तफा लोर्ड कर लिया है। भविष्य में मुझे अपने नए नाम जमीला लोर्ड पति मुस्तफा लोर्ड के नाम से जाना एवं पहचाना जाए।

पता-वार्ड नं.- 18, हाफिज कालोनी, बोहरा बाखल, मंदसौर (म.प्र.) 458001

कार्यालय सम्पदा प्रबंधक म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर

नामान्तरण —सूचना

मण्डल की आवासीय कॉलोनी रामटेकर की मंदसौर स्थित भवन क्रमांक 21/38 श्रीमती शारदा पाटीदार पति इन्द्रदेव पाटीदार को मण्डल आदेश क्रमांक 2201 दिनांक 22.02.1997 द्वारा नामांतरित किया गया था। उक्त भवन का सेलडीड दिनांक 28.02.1997 एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 01.07.2024 को उप- पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध कराया गया। श्रीमती शारदा पाटीदार पति इन्द्रदेव पाटीदार द्वारा उक्त भवन का विक्रय श्रीमती गुड्डिबाई पालीवाल पति श्री मनोहरलाल पालीवाल को कर विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2024 को इनके पक्ष में निष्पादित करवाया गया था। उक्त विक्रय पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भवन का नामांतरण श्रीमती गुड्डिबाई पालीवाल पति श्री मनोहरलाल पालीवाल अपने नाम करवाना चाहती है।

अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/परिवार के सदस्य/वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति/उर्जा हो तो वह विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में मय ठोस प्रमाण के कार्यालयों में प्रस्तुत करें समयावधि व्यतीत हो जाने पर उक्त भवन का नामान्तरण श्रीमती गुड्डिबाई पालीवाल पति श्री मनोहरलाल पालीवाल के नाम से कर दिया जावेगा उसके पश्चात कोई भी दावा/आपत्ति/उर्जा मान्य नहीं होगा।

सम्पदा प्रबंधक म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल मंदसौर (मप्र)



127 सिंचाई परियोजनाओं से 1 लाख 57 हजार हैक्टेयर में होगी सिंचाई

सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचे, बैठक संपन्न

मंदसौर, 05 नवम्बर गुरु एक्सप्रेस। जल उपयोगिता समिति की बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई जिले की 127 सिंचाई परियोजनाओं से 1 लाख 57 हजार 668 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक श्री विपिन जैन, सुवासरा विधायक श्री हरदीप सिंह डंग, गरोठ विधायक श्री चंदर सिंह सिसोदिया, कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग, सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश कुमार जैन, जल संसाधन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सीएमओ मौजूद थे।

बैठक में निर्देश दिए कि, सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचे। साथ ही कमियों को तुरंत दूर करें। समिधायक श्री चंदर सिंह के लिए व्यवस्थित प्लान बनाया जाए। बेहतर कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाए। गुणवत्ता से किसी प्रकार समझौता न करें। गोशालाओं को भी पानी मिले इसका भी ध्यान रखें। ऐसे तालाब जिनका पानी से कटाव हो रहा है, उनको चिन्हित कर मरम्मत करवाए। विभाग द्वारा

की जा रही कार्यवाही एवं गतिविधियों से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराए। सभी नगर परिषद समय-समय पर वसूली कार्यवाही पूर्ण करें। शामगढ-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से आगामी रबी सिंचाई में 85117 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित किया गया। गरोठ सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से 21 हजार 400 है. क्षेत्र में पिछले 04 वर्षों से सफलता पूर्व सिंचाई की जा रही है। भानपुरा नहर परियोजना से 13 हजार 354 है. क्षेत्र में पिछले 06 वर्षों से सफलता पूर्व सिंचाई की जा रही है। शामगढ-सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से आगामी रबी सिंचाई में 15000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु पम्प हाउस का परीक्षण 15 नवंबर तक किया जाएगा। परीक्षण के बाद 15 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। जल संसाधन विभाग, मंदसौर द्वारा गत वर्ष 148192 है. क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था, जिसके

विरुद्ध 148192 की सिंचाई की गई। विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई हेतु नहर से पानी की क्षति को रोकने के लिये नहर लाईनिंग, नए स्ट्रक्चर, मिट्टी का सुधार कार्य, मरम्मत, आदि कार्य लगातार किए जा रहे हैं। मंदसौर संभाग अंतर्गत लामगरा, खोडाना, ढिकोला, भरडावद निमज्जित तालाब के गेट सिंचाई के लिए नवंबर माह में खोले जाएंगे।

अन्नकूट प्रसादी उत्सव आज एक्सप्रेस। धनगर पुर्बिया समाज के श्री चारभुजा मंदिर पर अन्नकूट प्रसादी उत्सव का आयोजन आज दिनांक 6 नवम्बर 2024, बुधवार को प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। महाआरती के पश्चात अन्नकूट प्रसादी का भोग लगाकर प्रसादी वितरण होगा। ट्रस्ट अध्यक्ष श्री बंकट हप्पा ने समाजजन से कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील की है। उक्त जानकारी ट्रस्ट संयोजक विशाल चौहान ने दी।

कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान 57 ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनी



मंदसौर, 05 नवम्बर गुरु एक्सप्रेस। जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा सुशासन भवन सभाकक्ष में 57 ग्रामीणजनों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान निवासी दोषाडा के राजूलाल द्वारा कृषिभूमि में विद्युत डीपी व विद्युत कनेक्शन के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर द्वारा एमपीईबी को निर्देश दिये की आवेदक को डीपी व कनेक्शन जल्द प्रदाय करें। नवकार सिल्वर टाउनश्रीप कॉलोनी के निवासियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया कि कॉलोनी में नाले का पानी इकट्ठा होने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर द्वारा सीएमओ नगरपालिका को निर्देश दिये की नाले की सफाई करें। गरोठ के तेजमल द्वारा प्रोविजनल पेंशन एवं ग्रेजुएटी के भुगतान के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये की प्रोविजनल पेंशन एवं ग्रेजुएटी का भुगतान जल्द करें। ग्राम सेमली के तुलसीराम द्वारा जमीन पर कच्चा हटाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर द्वारा मंदसौर तहसीलदार को निर्देश दिये कि प्रार्थी की जमीन से कच्चा हटाकर भूमि प्रदान करें। जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुडवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने, निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, बीमारी सहायता, आपसी विवाद, शिक्षा ऋण दिलाने, सामुदायिक सुविधा घर (कम्युनिटी टायलेट) बनवाने आदि विषयों के आवेदन प्राप्त हुये। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत श्री राजेश कुमार जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल एवं जिला अधिकारी मौजूद थे।